EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

29 MAR - 4 APRIL 2026

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK RAILWAY Exam

EXAM Genius

UPSC | SSC | BANK | RAILWAY | STATE EXAMS

Ques: Japan International Cooperation Agency (JICA) signed ODA loan agreements with India worth approximately how much amount?

प्रश्न: जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) ने भारत के साथ लगभग कितनी राशि के ODA ऋण समझौते किए?

A) ¥150 billion
B) ¥200 billion
C) ¥300 billion
D) ¥275 billion
E) ¥350 billion

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

· Japan International Cooperation Agency signed Official Development Assistance (ODA) loan agreements worth ¥275 billion (approx ₹16,420 crore) with the Government of India.

· जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने भारत सरकार के साथ ¥275 बिलियन (लगभग ₹16,420 करोड़) के ODA ऋण समझौते किए।

· The funds will support major development projects across Punjab, Maharashtra, and Karnataka.

· यह राशि पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रमुख परियोजनाओं के लिए दी जाएगी।

· Key Projects include:

Maharashtra Healthcare Project: ¥62,294 million (₹3,708 crore approx.)
Punjab Climate-Resilient Horticulture Project: ¥18,684 million (₹1,112 crore approx.)
Bengaluru Metro Rail Phase 3: ¥102,480 million (₹5,500 crore approx.) for 44.65 km elevated corridors
Mumbai Metro Line 11: ¥92,400 million (₹6,100 crore approx.) for 17.51 km underground corridor

· These projects aim to improve healthcare, infrastructure, urban transport, and climate-resilient agriculture.

· इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्वास्थ्य, अवसंरचना, शहरी परिवहन और जलवायु-लचीली कृषि को मजबूत करना है।

Ques: RBI recently imposed penalties on which of the following entities for non-compliance with KYC and regulatory norms?

प्रश्न: RBI ने हाल ही में KYC और नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन के लिए किन संस्थाओं पर जुर्माना लगाया?

A) SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, Paytm / एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पेटीएम

B) Union Bank of India, Central Bank of India, Bank of India, Pine Labs / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पाइन लैब्स

C) Axis Bank, Yes Bank, Kotak Mahindra Bank, Razorpay / एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रेज़रपे

D) PNB, Canara Bank, IDBI Bank, PhonePe / पीएनबी, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, फोनपे

E) UCO Bank, Indian Bank, Bandhan Bank, BharatPe / यूको बैंक, इंडियन बैंक, बंधन बैंक, भारतपे

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Reserve Bank of India (RBI) imposed monetary penalties on Union Bank of India (₹95.40 lakh), Central Bank of India (₹63.60 lakh), Bank of India (₹58.50 lakh), and Pine Labs (₹3.10 lakh).

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (₹95.40 लाख), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (₹63.60 लाख), बैंक ऑफ इंडिया (₹58.50 लाख) और पाइन लैब्स (₹3.10 लाख) पर जुर्माना लगाया।

• The penalties were imposed for non-compliance with KYC norms, digital transaction rules, and lending practices.

• यह जुर्माना KYC नियमों, डिजिटल लेनदेन और ऋण संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया।

• Key issues included delay in crediting funds in unauthorized transactions

(Union Bank), failure to upload KYC records (Central Bank), improper charges & interest issues (Bank of India), and issuing PPIs without full KYC (Pine Labs).
• प्रमुख कारणों में अनधिकृत लेनदेन में देरी (Union Bank), KYC रिकॉर्ड अपलोड न करना (Central Bank), गलत शुल्क व ब्याज मुद्दे (Bank of India), और बिना पूर्ण KYC के PPI जारी करना (Pine Labs) शामिल हैं।
• The action reflects RBI's strict stance on customer protection, transparency, and regulatory compliance in banking and fintech sectors.
• यह कार्रवाई बैंकिंग और फिनटेक क्षेत्र में ग्राहक सुरक्षा, पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए RBI के सख्त रुख को दर्शाती है।

Ques: How much will the Government borrow in H1 FY27?
प्रश्न: सरकार H1 FY27 में कितनी राशि उधार लेगी?

A) ₹6.5 lakh crore / ₹6.5 लाख करोड़
B) ₹7.2 lakh crore / ₹7.2 लाख करोड़
C) ₹8.2 lakh crore / ₹8.2 लाख करोड़
D) ₹9.5 lakh crore / ₹9.5 लाख करोड़
E) ₹10 lakh crore / ₹10 लाख करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India will borrow ₹8.20 lakh crore during April–September FY 2026–27 through dated securities.
• भारत सरकार FY 2026–27 की अप्रैल–सितंबर अवधि में डेटेड सिक्योरिटीज के माध्यम से ₹8.20 लाख करोड़ उधार लेगी।
• This amount is about 51% of the total annual borrowing target of ₹16.09 lakh crore.
• यह कुल वार्षिक उधारी लक्ष्य ₹16.09 लाख करोड़ का लगभग 51% है।
• Borrowing will be conducted via 26 weekly auctions across multiple maturities ranging from 3 to 50 years.
• उधारी 3 से 50 वर्ष की अवधि वाली प्रतिभूतियों के माध्यम से 26 साप्ताहिक नीलामी द्वारा की जाएगी।
• ₹15,000 crore will be raised through Sovereign Green Bonds to support green

projects.
• ₹15,000 करोड़ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाए जाएंगे, जो हरित परियोजनाओं के लिए होंगे।
• Borrowing is mainly done through Government Securities (G-Secs) to manage fiscal deficit and fund expenditure.
• उधारी मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के माध्यम से की जाती है, जिससे राजकोषीय घाटा प्रबंधित होता है और सरकारी खर्च पूरा किया जाता है।

Ques: According to OECD, what is India's revised GDP growth forecast for FY 2026–27?

प्रश्न: OECD के अनुसार वित्त वर्ष 2026–27 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर क्या है?

A) 5.8%
B) 6.1%
C) 6.5%
D) 7.0%
E) 7.6%

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

· Organisation for Economic Co-operation and Development has revised India's GDP growth forecast downward by 10 basis points to 6.1% for FY 2026–27 in its Economic Outlook Interim Report.
· आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपने Economic Outlook Interim Report में भारत की GDP वृद्धि दर को 10 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.1% कर दिया है (FY 2026–27)।
· For FY 2025–26, the GDP growth rate is estimated at 7.6%.
· FY 2025–26 के लिए GDP वृद्धि दर 7.6% आंकी गई है।
· The revision reflects global economic uncertainties and changing macroeconomic conditions.

· यह संशोधन वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाता है।

About OECD :

· Founded: 30 September 1961 / 30 सितंबर 1961
· Headquarters: Paris / पेरिस
· Membership: 38 countries / 38 देश
· Secretary-General: Mathias Cormann / महासचिव: मैथियास कॉरमन

Ques: SEBI has extended the ban on futures trading in how many agricultural commodities till March 2027?
प्रश्न: सेबी ने मार्च 2027 तक कितनी कृषि वस्तुओं में फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर प्रतिबंध बढ़ाया है?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Securities and Exchange Board of India (SEBI) has extended the suspension of futures trading in certain agricultural commodities till March 31, 2027.
• सेबी ने कुछ कृषि वस्तुओं में फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर प्रतिबंध को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है।
• The ban was originally imposed in December 2021 to control rising food inflation.

• यह प्रतिबंध दिसंबर 2021 में बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था।

• The decision aims to curb speculative trading and reduce price volatility in essential food items.

• इस निर्णय का उद्देश्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं में सट्टेबाजी और कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम करना है।

• The suspension applies to 7 key agricultural commodities: Wheat, Moong, Paddy (Non-Basmati), Chana, Mustard Seeds, Soybean, and Crude Palm Oil.

• यह प्रतिबंध 7 प्रमुख कृषि वस्तुओं—गेहूं, मूंग, धान (नॉन-बासमती), चना, सरसों के बीज, सोयाबीन और कच्चा पाम तेल—पर लागू होता है।

• Futures trading involves buying and selling contracts for a future date, which can lead to speculative price movements.

• फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भविष्य की तारीख पर खरीद-बिक्री होती है, जिससे सट्टा आधारित मूल्य उतार-चढ़ाव हो सकता है।

• The move is expected to help stabilize food prices and protect consumers.

• इस कदम से खाद्य कीमतों को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा में मदद मिलेगी।

Ques: Lakshya Asset Management Company, recently approved by SEBI, is set to operate in which sector?

प्रश्न: हाल ही में SEBI से स्वीकृति प्राप्त लक्ष्या एसेट मैनेजमेंट कंपनी किस क्षेत्र में कार्य करेगी?

A) Insurance / बीमा

B) Banking / बैंकिंग

C) Telecom / दूरसंचार

D) Real Estate / रियल एस्टेट

E) Mutual Fund / म्यूचुअल फंड

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• Lakshya Asset Management Company has received approval from Securities and Exchange Board of India to start its Mutual Fund business in India.
• लक्ष्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से म्यूचुअल फंड व्यवसाय शुरू करने की मंजूरी मिली है।
• The company is sponsored by Wealth First Portfolio Managers, which is listed on National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange.
• यह कंपनी वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स द्वारा प्रायोजित है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।
• It will be the first Asset Management Company (AMC) headquartered in Ahmedabad, Gujarat.
• यह अहमदाबाद, गुजरात में मुख्यालय वाली पहली एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) होगी।

Ques: 'Payments Vision 2028' released by RBI primarily aims to focus on which area?

प्रश्न: आरबीआई द्वारा जारी 'पेमेंट्स विजन 2028' मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है?

A) Agricultural Credit Expansion / कृषि ऋण विस्तार
B) Digital Payments Ecosystem / डिजिटल भुगतान प्रणाली
C) Industrial Development / औद्योगिक विकास
D) Export Promotion / निर्यात प्रोत्साहन
E) Monetary Policy Reform / मौद्रिक नीति सुधार

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Reserve Bank of India (RBI) has released the 'Payments Vision 2028', outlining a 3-year roadmap for strengthening the digital payments ecosystem.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 'पेमेंट्स विजन 2028' जारी किया है, जो डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3-वर्षीय रोडमैप प्रस्तुत करता है।

• The vision focuses on enhancing safeguards, improving efficiency, and promoting user empowerment in digital payments.

• इस विजन का उद्देश्य भुगतान प्रणाली में सुरक्षा बढ़ाना, दक्षता सुधारना और उपयोगकर्ता सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

• RBI plans to introduce electronic cheques to modernize traditional payment systems.

• आरबीआई पारंपरिक भुगतान प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चेक शुरू करने की योजना बना रहा है।

• A Payments Switching Service (PaSS) is proposed to enable seamless transfer of payment instructions across banks.

• पेमेंट्स स्विचिंग सर्विस (PaSS) प्रस्तावित है, जिससे बैंकों के बीच भुगतान निर्देशों का आसान स्थानांतरण संभव होगा।

• A Shared Responsibility Framework will be introduced for handling unauthorized digital transactions.

• अनधिकृत डिजिटल लेनदेन के लिए साझा जिम्मेदारी ढांचा लागू किया जाएगा।

• RBI will implement a Domestic Legal Entity Identifier (DLEI) framework to improve transaction traceability.

• लेनदेन की ट्रेसबिलिटी बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (DLEI) ढांचा लागू किया जाएगा।

• A Cyber Key Risk Indicators (KRI) framework will be introduced for non-bank payment operators.

• गैर-बैंक भुगतान ऑपरेटरों के लिए साइबर की रिस्क इंडिकेटर्स (KRI) ढांचा लागू किया जाएगा।

• Regulatory oversight on digital payment platforms will be expanded for better compliance and security.

• डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स पर नियामक निगरानी बढ़ाई जाएगी ताकि बेहतर अनुपालन और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

• RBI will review cheque design and security features to enhance reliability.

• चेक के डिजाइन और सुरक्षा फीचर्स की समीक्षा की जाएगी ताकि विश्वसनीयता बढ़े।

• Full interoperability across Trade Receivables Discounting System (TReDS)

platforms will be explored to support MSMEs.

• MSMEs के लिए TReDS प्लेटफॉर्म्स के बीच पूर्ण इंटरऑपरेबिलिटी की संभावना तलाश की जाएगी।

Ques: RBI has set the WMA limit at ₹2,50,000 crore for which period?
प्रश्न: RBI ने ₹2,50,000 करोड़ की WMA सीमा किस अवधि के लिए निर्धारित की है?

A) Full FY 2026-27 / पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए

B) April–September 2026 / अप्रैल–सितंबर 2026

C) October–March 2027 / अक्टूबर–मार्च 2027

D) Calendar Year 2026 / कैलेंडर वर्ष 2026

E) Only April 2026 / केवल अप्रैल 2026

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI), in consultation with the Government of India, has set the WMA limit at ₹2,50,000 crore for the first half of FY 2026-27 (April–September 2026).

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत सरकार के साथ परामर्श करके FY 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल–सितंबर 2026) के लिए WMA सीमा ₹2,50,000 करोड़ तय की है।

• This helps the government manage short-term liquidity and cash flow mismatches.

• यह सरकार को अल्पकालिक नकदी और वित्तीय असंतुलन को प्रबंधित करने में मदद करता है।

• RBI may trigger fresh market loan issuance when 75% of the WMA limit is utilized.

• जब WMA सीमा का 75% उपयोग हो जाता है, तो RBI नए बाजार ऋण जारी कर सकता है।

• RBI retains the flexibility to revise the WMA limit based on prevailing economic conditions.

• RBI को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार WMA सीमा को संशोधित करने की स्वतंत्रता है।

• Interest rates: WMA is linked to the Repo Rate, while overdraft is charged at Repo Rate + 2%.

• ब्याज दर: WMA पर ब्याज रेपो रेट के बराबर होता है, जबकि ओवरड्राफ्ट पर रेपो रेट + 2% लिया जाता है।

About WMA (Ways and Means Advances):

• Purpose : Short-term borrowing facility for government
• उद्देश्य : सरकार के लिए अल्पकालिक उधारी सुविधा
• Governed by: Section 17(5) of RBI Act, 1934
• द्वारा शासित : RBI अधिनियम, 1934 की धारा 17(5)
• Type : Temporary liquidity support
• प्रकार : अस्थायी नकदी सहायता
• Interest Link : Repo Rate
• ब्याज संबंध : रेपो रेट
• Repayment Period : Within 90 days
• पुनर्भुगतान अवधि : 90 दिनों के भीतर

Ques: The Reserve Bank of India imposed a penalty of ₹231.80 lakh on which bank for non-compliance with disclosure norms?

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रकटीकरण नियमों के उल्लंघन के लिए ₹231.80 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया?

A) Paytm Payments Bank / पेटीएम पेमेंट्स बैंक

B) Jio Payments Bank / जियो पेमेंट्स बैंक

C) India Post Payments Bank / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

D) Fino Payments Bank / फिनो पेमेंट्स बैंक

E) Airtel Payments Bank / एयरटेल पेमेंट्स बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) imposed a penalty of ₹231.80 lakh on Airtel Payments Bank Limited.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर ₹231.80 लाख का जुर्माना लगाया।

• The penalty was due to non-compliance with guidelines related to disclosure in financial statements.

• यह जुर्माना वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण से संबंधित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया।

• RBI found that the bank failed to disclose certain customer complaints in its annual financial statements for FY 2024-25.

• RBI ने पाया कि बैंक ने FY 2024-25 के अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में कुछ ग्राहक शिकायतों का खुलासा नहीं किया।

Ques: For which period has the Government kept interest rates unchanged for small savings schemes like PPF and Sukanya Samriddhi?

प्रश्न: सरकार ने PPF और सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें किस अवधि के लिए अपरिवर्तित रखी हैं?

A) January–March 2026 / जनवरी–मार्च 2026

B) April–June 2026 / अप्रैल–जून 2026

C) July–September 2026 / जुलाई–सितंबर 2026

D) October–December 2026 / अक्टूबर–दिसंबर 2026

E) Full Year 2026 / पूरा वर्ष 2026

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Government has maintained interest rates for twelve small savings schemes for the April–June 2026 quarter.

• सरकार ने अप्रैल–जून 2026 तिमाही के लिए 12 छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी हैं।

• This marks the ninth consecutive quarter with no change in interest rates.

• यह लगातार नौवीं तिमाही है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

• The schemes include popular instruments like Public Provident Fund (PPF) and Sukanya Samriddhi Account.

• इन योजनाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि खाता जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं।

Interest Rates of Small Savings Schemes (April–June 2026) | ब्याज दरें:

• Post Office Savings Deposit : 4.0%
• 1-Year Time Deposit : 6.9%
• 2-Year Time Deposit : 7.0%
• 3-Year Time Deposit : 7.1%
• 5-Year Time Deposit : 7.5%
• 5-Year Recurring Deposit : 6.7%
• Senior Citizen Savings Scheme : 8.2%
• Monthly Income Account Scheme : 7.4%
• National Savings Certificate : 7.7%
• Public Provident Fund (PPF) : 7.1%
• Kisan Vikas Patra : 7.5% (matures in 115 months)
• Sukanya Samriddhi Account : 8.2%

About Small Savings Schemes:

• Regulated by : Government of India (Ministry of Finance)
• नियामक : भारत सरकार (वित्त मंत्रालय)
• Review Frequency : Quarterly
• समीक्षा : त्रैमासिक
• Objective : Encourage savings and provide secure investment options

• उद्देश्य : बचत को बढ़ावा देना और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करना

Ques: Moody's Investors Service has applied to establish a branch in which location to strengthen India's offshore financial ecosystem?

प्रश्न: Moody's Investors Service ने भारत के ऑफशोर वित्तीय केंद्र को मजबूत करने के लिए किस स्थान पर शाखा स्थापित करने के लिए आवेदन किया है?

A) Mumbai / मुंबई

B) GIFT City / गिफ्ट सिटी

C) Bengaluru / बेंगलुरु

D) Hyderabad / हैदराबाद

E) Chennai / चेन्नई

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Moody's Investors Service has applied to establish a branch in GIFT City to strengthen India's position as a global offshore financial centre.

• Moody's Investors Service ने भारत को वैश्विक ऑफशोर वित्तीय केंद्र बनाने के लिए गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने के लिए आवेदन किया है।

• The application has been filed under the IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2025.

• यह आवेदन IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2025 के तहत किया गया है।

• The proposed entity will undertake credit rating and related financial activities.

• प्रस्तावित इकाई क्रेडिट रेटिंग और संबंधित वित्तीय गतिविधियां संचालित करेगी।

• S&P Global Ratings has already received registration from IFSCA to operate in the IFSC.

• S&P Global Ratings को पहले ही IFSCA से IFSC में संचालन की अनुमति मिल चुकी है।

• Among domestic agencies, CARE Ratings (CareEdge) was the first to set up a base in GIFT IFSC through its subsidiary in October 2024.

• घरेलू एजेंसियों में CARE Ratings (CareEdge) ने अक्टूबर 2024 में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से GIFT IFSC में सबसे पहले आधार स्थापित किया।

• Moody's is one of the "Big Three" global credit rating agencies along with S&P Global Ratings and Fitch Ratings.

• Moody's विश्व की "Big Three" क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है, जिसमें S&P Global Ratings और Fitch Ratings भी शामिल हैं।

About GIFT City (IFSC):

• Full Form : Gujarat International Finance Tec-City
• पूरा नाम : गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी
• Location : Gandhinagar, Gujarat
• स्थान : गांधीनगर, गुजरात
• Regulator : International Financial Services Centres Authority (IFSCA)
• नियामक : अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA)
• Purpose : Develop India as a global financial services hub
• उद्देश्य : भारत को वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित करना

Ques: According to ICRA, what is the projected GDP growth rate of India for FY 2026-27?

प्रश्न: ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है?

A) 5.5%
B) 6.0%
C) 6.5%
D) 7.0%
E) 7.6%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• ICRA has projected that India's GDP growth will moderate to 6.5% in FY 2026-27.
• ICRA ने अनुमान लगाया है कि FY 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% तक घट सकती है।
• This is lower than the 7.6% growth estimated for the current financial year.
• यह वर्तमान वित्त वर्ष के अनुमानित 7.6% की तुलना में कम है।
• The moderation indicates a gradual slowdown in economic growth.
• यह आर्थिक वृद्धि में धीरे-धीरे कमी का संकेत देता है।

About ICRA Limited:

• Founded : 1991
• स्थापना : 1991
• Headquarters : Gurugram, Haryana
• मुख्यालय : गुरुग्राम, हरियाणा
• Type : Credit Rating Agency
• प्रकार : क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
• Function : Provides credit ratings, research, and risk assessment services
• कार्य : क्रेडिट रेटिंग, शोध और जोखिम मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करना

Ques: India's Index of Industrial Production (IIP) growth rate in February 2026 stood at what percentage?

प्रश्न: फरवरी 2026 में भारत की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) वृद्धि दर कितनी रही?

A) 4.5%
B) 5.0%
C) 5.8%
D) 6.0%
E) 5.2%

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• India's industrial growth, measured by the Index of Industrial Production (IIP), rose to 5.2% in February 2026.

• भारत की औद्योगिक वृद्धि, जिसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) से मापा जाता है, फरवरी 2026 में 5.2% रही।

• This shows a slight increase from 5.1% recorded in January 2026.

• यह जनवरी 2026 में दर्ज 5.1% की तुलना में थोड़ा अधिक है।

• The growth was driven by strong performance in the manufacturing sector.

• इस वृद्धि का मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन रहा।

• Manufacturing sector output growth accelerated to 6% in February 2026.

• फरवरी 2026 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 6% तक पहुंच गई।

• The data was released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

• यह आंकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए।

About Index of Industrial Production (IIP):

• Measures : Industrial output in sectors like manufacturing, mining, and electricity

• मापता है : विनिर्माण, खनन और बिजली जैसे क्षेत्रों का उत्पादन

• Base Year : 2011-12

• आधार वर्ष : 2011-12

• Released by : NSO (Ministry of Statistics)

• जारीकर्ता : NSO (सांख्यिकी मंत्रालय)

• Frequency : Monthly

• आवृत्ति : मासिक

Ques: The RBI has mandated the use of UTI for which type of financial transactions?

प्रश्न: आरबीआई ने किस प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए UTI का उपयोग अनिवार्य किया है?

A) Government Securities Market (सरकारी प्रतिभूति बाजार)

B) Foreign Exchange Spot Transactions (विदेशी मुद्रा स्पॉट लेनदेन)

C) All OTC Derivatives Transactions (सभी OTC डेरिवेटिव लेनदेन)

D) Equity Market Transactions (इक्विटी बाजार लेनदेन)

E) Mutual Fund Transactions (म्यूचुअल फंड लेनदेन)

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has mandated the use of Legal Entity Identifier (LEI) and Unique Transaction Identifier (UTI) for financial market transactions.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय बाजार लेनदेन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (LEI) और यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर (UTI) का उपयोग अनिवार्य किया है।

• LEI is effective immediately, while UTI will be applicable from January 1, 2027.

• LEI तत्काल प्रभाव से लागू है, जबकि UTI 1 जनवरी 2027 से लागू होगा।

• The 20-character LEI is required for non-individual entities in OTC, government securities, and foreign exchange markets.

• 20 अक्षरों वाला LEI, OTC, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा बाजारों में गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए आवश्यक है।

• The up-to-52-character UTI is mandated for all over-the-counter (OTC) derivatives transactions.

• 52 अक्षरों तक का UTI सभी ओवर-द-काउंटर (OTC) डेरिवेटिव लेनदेन के लिए अनिवार्य किया गया है।

• These identifiers are global standards aimed at enhancing transparency in financial markets.
• ये पहचानकर्ता वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वैश्विक मानक हैं।
• LEI will also apply to users undertaking non-derivative foreign exchange transactions.
• गैर-डेरिवेटिव विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाले उपयोगकर्ताओं पर भी LEI लागू होगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी (RBI):

• RBI Foundation Day – 1 April 1935
• स्थापना दिवस – 1 अप्रैल 1935
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• Governor – Sanjay Malhotra
• गवर्नर – संजय मल्होत्रा

Ques: The RBI has capped banks' net open positions in the rupee at what amount per day?
प्रश्न: RBI ने बैंकों की रुपये में नेट ओपन पोजीशन की सीमा प्रति दिन कितनी तय की है?

A) $50 million / 50 मिलियन डॉलर
B) $75 million / 75 मिलियन डॉलर
C) $100 million / 100 मिलियन डॉलर
D) $150 million / 150 मिलियन डॉलर
E) $200 million / 200 मिलियन डॉलर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has capped banks' net open positions in the

rupee at $100 million at the end of each business day.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों की रुपये में नेट ओपन पोजीशन को प्रति दिन $100 मिलियन तक सीमित कर दिया है।

• This move is aimed at tightening oversight in the foreign exchange market amid the rupee hitting record lows.

• यह कदम रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बीच विदेशी मुद्रा बाजार में निगरानी मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

• RBI has directed authorised dealers of foreign currency to comply with the rule by April 10.

• RBI ने अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलरों को 10 अप्रैल तक इस नियम का पालन करने का निर्देश दिया है।

About Net Open Position (NOP):

• Meaning : Difference between foreign currency assets and liabilities held by banks

• अर्थ : बैंकों द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर

• Purpose : Manage exchange rate risk and ensure market stability

• उद्देश्य : विनिमय दर जोखिम को नियंत्रित करना और बाजार की स्थिरता बनाए रखना

• Regulated by : RBI

• नियंत्रक : RBI

Ques: In which year was the Reserve Bank of India (RBI) established?

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A) 1930 / 1930
B) 1932 / 1932
C) 1935 / 1935
D) 1947 / 1947
E) 1950 / 1950

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) was established on April 1, 1935 under the RBI Act, 1934 based on the recommendations of the Hilton Young Commission.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI Act, 1934 के तहत हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों पर हुई थी।

• RBI regulates and supervises India's banking system and acts as the central bank of the country.

• RBI भारत की बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित एवं संचालित करता है और देश का केंद्रीय बैंक है।

• The headquarters was permanently shifted to Mumbai in 1937 (initially in Calcutta).

• मुख्यालय को 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया (प्रारंभ में कोलकाता में था)।

• First Governor: Sir Osborne Smith | First Indian Governor: C.D. Deshmukh | Current Governor: Sanjay Malhotra.

• प्रथम गवर्नर: सर ऑस्बोर्न स्मिथ | प्रथम भारतीय गवर्नर: सी.डी. देशमुख | वर्तमान गवर्नर: संजय मल्होत्रा।

• RBI is governed by a Central Board of Directors consisting of one Governor, up to four Deputy Governors and other directors (appointed for 4 years).

• RBI का संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें एक गवर्नर, अधिकतम चार डिप्टी गवर्नर और अन्य निदेशक होते हैं (4 वर्ष के लिए नियुक्त)।

• RBI also served as the central bank for Burma (Myanmar) till 1947 and Pakistan till June 1948.

• RBI ने 1947 तक बर्मा (म्यांमार) और जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया।

• Currency printing is handled by Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt Ltd (BRBNMPL) at Mysore and Salboni.

• मुद्रा छपाई का कार्य भारतीया रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) द्वारा मैसूर और सालबोनी में किया जाता है।

• RBI has five subsidiaries: DICGC, BRBNMPL, ReBIT, IFTAS and RBIH.

• RBI की पाँच सहायक कंपनियाँ हैं: DICGC, BRBNMPL, ReBIT, IFTAS और RBIH।

Ques: As per RBI's directive, Two-Factor Authentication (2FA) for all digital transactions became effective from which date?

प्रश्न: RBI के निर्देश के अनुसार सभी डिजिटल लेनदेन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) किस तिथि से प्रभावी हुआ?

A) January 1, 2026 / 1 जनवरी 2026

B) March 31, 2026 / 31 मार्च 2026

C) April 1, 2026 / 1 अप्रैल 2026

D) July 1, 2026 / 1 जुलाई 2026

E) April 1, 2027 / 1 अप्रैल 2027

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Two-Factor Authentication (2FA) for all digital transactions became effective from April 1, 2026.

• सभी डिजिटल लेनदेन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया।

• The directive was issued by the Reserve Bank of India (RBI).

• यह निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किया गया था।

• It applies to all digital transactions, including UPI platforms.

• यह UPI सहित सभी डिजिटल लेनदेन पर लागू है।

• The ecosystem has primarily adopted SMS-based OTP as the second authentication factor.

• इकोसिस्टम ने मुख्य रूप से SMS-आधारित OTP को दूसरे सत्यापन कारक के रूप में अपनाया है।

• Users must now verify transactions through OTP, fingerprint, or facial recognition in addition to UPI PIN.

• अब उपयोगकर्ताओं को UPI PIN के अलावा OTP, फिंगरप्रिंट या फेशियल रिकग्निशन से भी लेनदेन सत्यापित करना होगा।

• Screenshots and screen recording are restricted in banking apps to prevent fraud.

• धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकिंग ऐप्स में स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

• The initiative aims to reduce fraud and improve accountability in digital payments.

• इस पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी को कम करना और जवाबदेही बढ़ाना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• RBI Established – 1 April 1935

• RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935

• RBI Nationalised – 1 January 1949

• RBI का राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949

• Headquarters – Mumbai

• मुख्यालय – मुंबई

• Current RBI Governor – Sanjay Malhotra

• वर्तमान RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा

• Deputy Governors – M. Rajeshwar Rao, T. Rabi Sankar, Swaminathan J., Poonam Gupta

• उप गवर्नर – एम. राजेश्वर राव, टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जे., पूनम गुप्ता

Ques: India's gross GST collections in March 2026 crossed which milestone, showing an 8.8% growth compared to March 2025?

प्रश्न: मार्च 2026 में भारत का सकल GST संग्रह 8.8% की वृद्धि के साथ किस स्तर को पार कर गया?

A) ₹1.5 lakh crore / ₹1.5 लाख करोड़

B) ₹1.75 lakh crore / ₹1.75 लाख करोड़

C) ₹2 lakh crore / ₹2 लाख करोड़

D) ₹2.5 lakh crore / ₹2.5 लाख करोड़

E) ₹3 lakh crore / ₹3 लाख करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India's gross GST collections recorded a growth of 8.8% in March 2026 compared to the same month last year.

• भारत का सकल GST संग्रह मार्च 2026 में पिछले वर्ष के समान महीने की तुलना में 8.8% बढ़ा।

• The collections crossed the ₹2 lakh crore mark, indicating strong economic activity and better compliance.

• संग्रह ₹2 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया, जो मजबूत आर्थिक गतिविधि और बेहतर अनुपालन को दर्शाता है।

• For the financial year 2025-26, gross GST revenues reached ₹22 lakh crore.

• वित्तीय वर्ष 2025-26 में सकल GST राजस्व ₹22 लाख करोड़ तक पहुँच गया।

• This marks an increase of 8.3% over ₹20 lakh crore recorded in the previous financial year.

• यह पिछले वित्तीय वर्ष के ₹20 लाख करोड़ की तुलना में 8.3% की वृद्धि दर्शाता है।

• The data was released by the Ministry of Finance.

• यह आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• GST Implemented – 1 July 2017

• GST लागू – 1 जुलाई 2017

• Constitutional Amendment – 101st Constitutional Amendment Act, 2016

• संवैधानिक संशोधन – 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016

• GST Council Head – Union Finance Minister

• GST परिषद प्रमुख – केंद्रीय वित्त मंत्री

Ques: As per RBI's revised capital market exposure norms, what is the cap on loans for subscribing to shares through IPOs or ESOPs per individual?

प्रश्न: RBI के संशोधित पूंजी बाजार एक्सपोजर नियमों के अनुसार, IPO या ESOP के माध्यम से शेयर सदस्यता के लिए प्रति व्यक्ति ऋण की सीमा क्या है?

A) ₹10 lakh / ₹10 लाख

B) ₹20 lakh / ₹20 लाख

C) ₹25 lakh / ₹25 लाख

D) ₹50 lakh / ₹50 लाख

E) ₹1 crore / ₹1 करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• RBI has capped loans for purchase of shares and other eligible securities at ₹1 crore per borrower across the banking system.

• RBI ने पूरे बैंकिंग सिस्टम में शेयर और अन्य पात्र प्रतिभूतियों की खरीद के लिए ऋण सीमा प्रति उधारकर्ता ₹1 करोड़ तय की है।

• Earlier, this limit was ₹20 lakh, which has now been increased to ₹1 crore.

• पहले यह सीमा ₹20 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है।

• However, for IPOs, Follow-on Public Offers (FPOs) and ESOPs, the borrowing limit is restricted to ₹25 lakh per individual.

• हालांकि IPO, FPO और ESOP के लिए उधार लेने की सीमा प्रति व्यक्ति ₹25 लाख निर्धारित की गई है।

• The revised capital market exposure rules have been deferred by 3 months—from April 1 to July 1, 2026.

• संशोधित पूंजी बाजार एक्सपोजर नियमों को 3 महीने के लिए 1 अप्रैल से 1 जुलाई 2026 तक स्थगित किया गया है।

• The deferral was due to operational and interpretational concerns raised by banks and market participants.

• यह स्थगन बैंकों और बाजार प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए परिचालन और व्याख्यात्मक मुद्दों के कारण दिया गया।

• The move aims to prevent excessive leverage, curb speculative borrowing and reduce risks in the banking system.

• इस कदम का उद्देश्य अत्यधिक लीवरेज को रोकना, सट्टा उधारी पर नियंत्रण और बैंकिंग जोखिम को कम करना है।

• RBI also clarified that acquisition finance now includes mergers and amalgamations.

• RBI ने स्पष्ट किया कि अधिग्रहण वित्त में अब विलय और समामेलन भी शामिल होंगे।

• Banks must obtain a corporate guarantee from the acquiring company when financing subsidiaries or SPVs.

• जब बैंकों द्वारा सहायक कंपनियों या SPV को वित्त दिया जाता है, तो अधिग्रहणकर्ता कंपनी से कॉर्पोरेट गारंटी लेना अनिवार्य होगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• IPO Full Form – Initial Public Offering
• IPO का पूर्ण रूप – प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम
• FPO Full Form – Follow-on Public Offer
• FPO का पूर्ण रूप – फॉलो-ऑन सार्वजनिक प्रस्ताव
• ESOP Full Form – Employee Stock Option Plan
• ESOP का पूर्ण रूप – कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना
• SPV Full Form – Special Purpose Vehicle
• SPV का पूर्ण रूप – विशेष प्रयोजन वाहन
• Capital Market Regulator – SEBI
• पूंजी बाजार नियामक – सेबी
• SEBI Headquarters – Mumbai
• सेबी मुख्यालय – मुंबई
• SEBI Chairman – Tuhin Kanta Pandey
• सेबी अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडेय